W (ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कोई कदम उठा रही हैं,

(ग) क्या बैंक अधिकारियों द्वारा आवेनदन-पत्र स्वीकार किए जाने के संबंध में परेशान किए जाने संबंधी कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं, और

(ड़) गत दो वर्षो के दौरान राज्य-वार कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) राज्य/केन्द्र शासित सरकारों को आवेदनों प्राप्ति के बाद एक महीने के भीतर उन पर कार्यवाही करने की सलाह दी गई हैं । बैंकों को 25,000 रूपये तक के ऋण आवेदन-पत्रों का निपटान एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रुपये से अधिक से आवेदन-पत्रों का निपटान 8 से 9 सप्ताह के भीतर करना होता हैं । कुल मिलाकर, बैंक निर्धारित समय सीमा की भीतर आवेदनों का निपटान करते हैं । बैंको में आवेदनों के ढेर न लगे, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने एक प्रायोजना अनुसूची शेडयूल आफ स्पांसरिंग भी निर्धारित की हैं ।

(ग) से (ड़) जब भी शिकायते प्राप्त होती हैं, उनके समाधान के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के साथ मामले को उठाया जाता हैं ।

Scrapping of IDRA, 1951

2992. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to scrap the Industries Development Regulation Act, 1951; and

(b) if so, the details thereof and reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Investment by liquor and tabacco companies

2993. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have invited specially the giant liquor and tobacco companies to invest in our country;

(b) if so, what are the reasons for this special effort;

(c) whether Central Trade Unions have protested against the entry of such MNCs into the country; and

(d) if so, the details thereof;

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Yes, Sir. Some Central Trade Unions have represented against entry of Foreign Companies into the tabacco sector on the ground that it would lead to unemployment of bidi workers. However, several Tobacco Grower Associations have supported the entry of foreign companies into tobacco sector on the ground that farmers would get better returns for their crops.

Sale of Units of CCI

2994. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of units of Cement Corporation of India which have been sold or are going to be sold along-with their names;

(b) the number of units which will remain with CCI after this sale deed alongwith their names;

(c) whether Government are aware that most of the units of CCI have become sick due to mismangament by its Chairman and Managing Director in the last few years; and

(d) if so, what steps have been taken by Government to remove this mismanagement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) Yerraguntla unit of CCI has been sold to M/s. India Cement Limited (ICL) at a cost of Rs. 200.70 cr. on open tender basis and physical possession was handed over on 21.1.98. Three other units vis. Charkhi Dadri, Mandhar and Akaltara which had been identified by the BIFR in the Draft Rehabilitation Scheme circulated by them, are proposed to be sold.

(b) If the proposed sale of 3 Units materializes, 7 units i.e. Bokajan, Rajban, Tandur, Kurkunta, Adilabad, Nayagaon and Nayagaon Expansion including Delhi Grinding Unit will remain with CCI.

(c) and (d) Most of the units of CCI have become sick due to various reasons resulting in continuous losses and BIFR is already seized of the problem of rehabilitating the Company.

खादी उद्योग द्वारा डेनिस जींस का उत्पादन

2995. **श्री रमा शंकर कौशिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खादी उद्योग नई पीढ़ी में खादी की लोकप्रियता बढ़ाने की दृष्टि से डेनिस जींस का उत्पादन करने पर विचार कर रहा हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में एक नया कपड़ा यानी "डेनिस कपड़ा" निकाला हैं ।

(ख) ग्राहकों को नये उत्पाद की पेशकश करने के इरादे से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हाथ से कताई किए गए धागे का प्रयोग करके हाथ से बुने हुए खादी के डेनिस कपड़े का विकास किया हैं । लोगों को इस विकास के बारे में जानकारी देने तथा खादी उत्पादनकारी एजेंसियों को डेंनिस का उत्पादन आरंभी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "स्वदेशी मेले" में यह बुनाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की गयी थी । सतत् उत्पादन पद्धति बनाने के उद्देश्य से सात संस्थाओं वाणिज्यिक उत्पादन आरंभी करने के लिए चुना गया हैं जिनमें से प्रत्येक के लिए प्रति वर्ष 2000 मीटर प्रारभिंक लक्ष्य रखा गया हैं । यह उत्पादन 2 अक्तूबर, 1999 को आरंभ किए जाने की आशा हैं ।

उत्तर प्रदेश में जूता उत्पादकों को सहायता

2996. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी :** क्या उद्योग मंत्रीय ह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जूता उत्पादकों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से यू0 एन0 डी0 पी0 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को स्वीकृत 48.00 करोड़ रुपए की धनराशि में से 45.00 करोड़ रुपए की मांग की हैं,

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय उद्योग विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व प्रदान करते हुए केन्द्र सरकार के अंश के रूप में 22.50 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं,

(ग) यदि हां, तो राज्य के जूता निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों को कब क स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए जून 1998 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । तब से दिसम्बर, 1999 तक आगरा तथा कानपुर के पादुका (फुटवियर) कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए और कानपुर जीनसाजी क्षेत्र की सहायता हेतु राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत 256,000 अमरीकी डालर की रकम आबंटित की गई हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

TRIPS agreement

2997. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the Minister of INDUS TRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that TRIP'S Agreement allows examination of product